THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMEN (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The NCR Planning Board has submitted investment proposals amounting to Rs. 2840 crores for the 8th Five Year Plan for consideration of the Planning Commission.

(b) The proposals of the Board, *inter- alia, include development of* 8 priority towns|complexes (Panipat, Rohtak, Palwal, Rewari-Dharuhera-Bhiwadi Complex, Meerut, Hapur, Bulandsher-Khurja Complex & Alwar), six DMA towns (Faridabad-Ballabhgarh, Bahadurgarh, Gurgaon. Ghaziabad-Loni, NOIDA and Kundli) and five countermegnet Areas (Hissar, Patiala, Barilly, Gwalior and Kota).

(c) and (d) The Eighth Plan is yet to be finalised by the Planning Commission.

Revival Plan for National Projects Construction Corporation

@2685. SHRI N. E. BALARAM: SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the joint employees forum, of the National Project. Construction Corporation Limited has submitted a revival plan for the company; and

(b) if so. the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) The revival plan submitted by Joint Employees Forum of National Projects Construction Corporation Limited broadly seeks realisation of an amount of Rs. 24 crores and award of new works worth Rs. 150 crores with Government assistance by March, 1992; increase in cash credit limit by Rs. 20 crores till March, 1993; structural adjustment in organisational set up and setting up of a governing body comprising of representatives of employees to manage the affairs of the Corporation through a Board comprising of technical and professional managers.

Reopening of stationery office

2686. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1580, given in the Rajya Sabha on the 6th December, 1991 and state:

(a) whether Government have since taken a decision to restart the functioning of Government of India Stationery Office; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Revival Plan for NPCC

2687. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the employees of the National Projects Construction Corporation have submitted a viability plan for the revival of the company by proposing to run it through worker's cooperative and by hiring professional managers to run the company; and

(b) if so what is the reaction of Government to the suggestion and what progress has been made in regard to the viability revival?

@Previously Unstarred Question 1273, transferred from the 5th March, 1992.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The revival plan submitted by Joint Employees Forum of National Projects Construction Corporation Limited, instead of running the Company through worker's cooperative, seeks among other things, setting up of a governing body consisting of representatives of all sections of employees to manage the affairs of the Corporation through a Board comprising of technical and professional managers.

(b) The viability of the proposal is under examination.

राजस्थान में बिलासपुर (टोंक) परियोजना का निर्माण

2688. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में निर्माणाधीन बिलासपुर परियोजना (टोंक) को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या पर्यावरणीय दृष्टि से इस परियोजनाका कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अधीन सड़कों के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी है ;

(च) क्या सरकार को इस परियोजना के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 328 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की संशोधित बिलासपुर परियोजना जिसमें जल आपूर्ति और सिंचाई घटक शामिल है नवम्बर 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। हालांकि इसके जल वैज्ञानिक पहलुओं को निर्बाधित किया गया है, लेकिन राज्य को अन्य पहलुओं को हल करना है, विशेषकर शहरी विकास मंत्रालय के टिप्पणियों के संबंध के जिनकी अनुपालना से परियोजना का कार्यक्षेत्र के परिवर्तन होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने स्थिति रिपोर्ट तथा पर्यावरण और पारिस्थिति की हेतु कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रबंध अध्ययन केन्द्र, हरीश चन्द माथुर, राजस्थान राज्य जन प्रशासन संस्थान को सौंपा है ।

(ङ) चूंकि यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है इसलिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उसमें वन भूमि का अनारक्षण शामिल न हो ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं/जलाशयों और बांधों को शुरू किया जाना

2689. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं जलाशय/बांध शुरू किए गए है और कौन-कौन सी परियोजनाएं अभी विचाराधीन है ; और

(ख) किन किन परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण